

निजी कॉर्पोरेट निवेश: कार्यनिष्पादन और निकट - अवधि दृष्टिकोण

श्रेया भान[^], राजेंद्र एन चौहान[^] और राजेश बी कावेडिया[^] द्वारा

भारत में निजी निवेश गतिविधि के लिए निकट-अवधि दृष्टिकोण का अनुमान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के परियोजना निवेश प्रस्तावों से लगाया जाता है। हाल की अवधि में बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि, बढ़ता क्षमता उपयोग, बेहतर व्यावसायिक दृष्टिकोण और मांग की स्थिति एवं निवेश गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विभिन्न सरकारी नीतिगत पहलों ने निजी कंपनियों को अखिल भारतीय स्तर पर नई पूंजी निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की परिकल्पित कुल लागत 2014-15 से 2022-23 के दौरान एक नए शिखर पर पहुंच गई। 2022-23 के दौरान कुल पूंजी निवेश का लगभग 40 प्रतिशत 2023-24 में व्यय होने की उम्मीद है। एक दीर्घकालिक विश्लेषण निजी पूंजीगत व्यय के आकलन के प्रारंभिक संकेतक के रूप में निजी कंपनियों के निवेश इरादों की उपयोगिता की ओर इशारा करता है।

परिचय

आम तौर पर, निवेश और खपत भारत की विकास कहानी के प्रमुख चालक बने रहे। 2013-14 से निवेश में मंदी का अनुभव करने के बाद, पूंजीगत व्यय चक्र, विशेष रूप से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत 2021-22 से देखे गए थे, जो सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित थे। विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोग में सुधार, ऋण मांग में तेजी, मांग की स्थिति में सुधार और उपभोक्ता भावना पूंजीगत व्यय चक्र के लिए अच्छा संकेत है। कंपनियों और बैंकों दोनों द्वारा बैलेंस शीट को व्यवस्थित करने से उधार गतिविधियों को बढ़ाने की गुंजाइश दिखती है। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) एक

[^] लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग से हैं। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। श्रृंखला का पिछला लेख "निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 के लिए दृष्टिकोण" भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अगस्त 2022 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है जो अर्थव्यवस्था के भीतर निवेश के माहौल को दर्शाता है। यह निजी निवेश दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण करके आर्थिक विस्तार की क्षमता का मूल्यांकन करने के महत्व को रेखांकित करता है। निगमों द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने में समय अंतराल को देखते हुए, संभावित योजना के लिए एक भविष्योन्मुखी निवेश दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए पूरी तरह से बैलेंस शीट-आधारित निवेश मूल्यांकन पर निर्भर रहना एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। कई अर्थव्यवस्थाओं में, सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण आमतौर पर इच्छित कॉर्पोरेट निवेश योजनाओं और निवेश भावना पर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में नियोजित किया जाता है। ये सर्वेक्षण वर्तमान निवेश वातावरण और प्रत्याशित निवेश इरादों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो निकट से मध्यम अवधि में साकार होने की उम्मीद है।

भारत भी 1980 के दशक के उत्तरार्ध से निजी निवेश के आकलन और पूर्वानुमान/नाउकारस्टिंग के लिए चुनिंदा बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई)¹ से निजी कंपनियों के परियोजना वित्त आंकड़ों के बारे में नियमित रूप से जानकारी एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक निवेश² पर दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की पूंजीगत व्यय योजनाओं पर नजर रख रहा है।

लेख को छह खंडों में संरचित किया गया है। खंड II कार्यप्रणाली और उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। समीक्षा की अवधि (अर्थात्, 2022-23) के दौरान स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनके वित्त पोषण और क्षेत्रों और उद्योगों के संदर्भ में वितरण संबंधी पहलुओं को खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV स्वीकृत/अनुबंधित ऋणों/वित्तपोषण की चरणबद्ध रूपरेखा से संबंधित है और कॉर्पोरेट

¹ सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो परियोजना वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एकजम)।

² निजी कंपनियों के निवेश दृष्टिकोण का विश्लेषण नियमित रूप से प्रारंभ में आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक में और 1989 से भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में आलेखों के रूप में जारी किया जाता है।

निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाती है। परिकल्पित पूंजीगत व्यय और निजी कंपनियों के सकल स्थायी पूंजी निर्माण का विश्लेषण खंड V में प्रस्तुत किया गया है, जबकि खंड VI अध्ययन का समापन करता है।

II. कार्यप्रणाली और सीमाएं

निजी कंपनियों की निवेश गतिविधियों के निकट अवधि के दृष्टिकोण के आकलन के लिए रंगराजन (1970)³ द्वारा प्रस्तावित पद्धति को अपनाया गया है। इस उद्देश्य के लिए, निवेश के इरादों पर डेटा तीन अलग-अलग स्रोतों के माध्यम से एकत्र किया गया था, अर्थात्, (i) बैंक और वित्तीय संस्थान जो निजी कंपनियों के परियोजना वित्त व्यवसाय में शामिल हैं, (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से पूंजीगत व्यय के उद्देश्य के लिए जुटाए गए वित्त [विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), रुपया मूल्य वर्ग के बांड (आरडीबी) के निर्गम सहित], और (iii) प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से निजी कंपनियों द्वारा एक वर्ष के दौरान अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) और राइट्स इश्यू।

दोहरी गिनती और इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश के अधिक आकलन से बचने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक परियोजना को डेटासेट में केवल एक बार शामिल किया जाए। यह रिजर्व बैंक के आंतरिक डेटाबेस का उपयोग करके और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी को शामिल करके प्राप्त किया जाता है, भले ही किसी परियोजना को कई स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। यह अध्ययन विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर केंद्रित है जो उपरोक्त स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं, जिनकी परियोजना लागत ₹ 10 करोड़ से अधिक है, और निजी कॉर्पोरेट्स के साथ परियोजना की अधिकांश स्वामित्व हिस्सेदारी है। केंद्र और/या राज्य सरकारों के साथ बहुसंख्यक हिस्सेदारी रखने वाली परियोजनाओं और न्यास और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को इस अध्ययन के दायरे से बाहर रखा गया है।

³ इस पद्धति को 19 दिसंबर, 1970 को डॉ सी रंगराजन द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सामाहिक (ईपीडब्ल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में लिखे गए आलेख "कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का पूर्वानुमान" में प्रकाशित किया गया था।

अनुमान इस धारणा के तहत निकाले गए हैं कि कंपनियां अपनी पूर्व-पूंजीगत व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएस) में रिपोर्ट किए गए निजी कंपनियों के वास्तविक निश्चित निवेश आंकड़ों से भिन्न हैं, क्योंकि कुछ नियोजित इरादे उनकी राशि और समय के संदर्भ में वास्तविक निवेश में साकार नहीं हो सकते हैं, और यह निश्चित है कि कुछ परियोजनाओं को आंतरिक संसाधनों के साथ-साथ पूंजी बाजार/बॉन्ड वित्तपोषण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से उठाए गए धन के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है जिन्हें आरबीआई द्वारा एकत्र किए गए परियोजना वित्त आंकड़ों में शामिल नहीं किया जा रहा है।

III. स्वीकृत/अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं

बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या के साथ-साथ कुल परियोजना लागत के संदर्भ में परिलक्षित निजी कंपनियों के निवेश दृष्टिकोण में 2022-23 के दौरान सुधार जारी रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,41,976 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाली 401 परियोजनाओं की तुलना में 2022-23 के दौरान लगभग 547 परियोजनाओं को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता मिली, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹ 2,66,547 करोड़ है (अनुबंध सारणी ए1)।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तपोषण नहीं लेने वाली 393 कंपनियों ने ईसीबी के जरिये ₹ 82,448 करोड़ जुटाए, जबकि 42 अन्य कंपनियों ने अपने पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए आईपीओ के द्वारा घरेलू इक्विटी निर्गम के जरिये ₹ 3,629 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 2022-23 के दौरान ₹ 3,52,624 करोड़ के रिकॉर्ड पूंजी परिव्यय के साथ 982 परियोजनाओं की निवेश योजनाएं बनाई गईं, जो 2014-15 के बाद से देखे गए स्तर से अधिक है, जबकि 2021-22 में ₹ 1,96,445 रुपये के निवेश के इरादे के साथ 791 परियोजनाएं थीं (अनुबंध सारणी ए 1-ए 4)।

i) आकार के अनुसार

परियोजनाओं के आकार-वार वितरण ने विभिन्न आकारों में परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2022-23 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत आठ मेगा

परियोजनाएं (परियोजना लागत ₹ 5,000 करोड़ और अधिक) और 68 बड़ी परियोजनाएं (₹ 1000 करोड़ - ₹ 5000 करोड़) थीं, जिनकी कुल परियोजना लागत में क्रमशः 27.1 प्रतिशत और 41.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। मेगा/बड़ी परियोजनाओं की चरणबद्ध योजना का दीर्घावधि में पूंजीगत व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है (अनुलग्नक सारणी ए5)।

ii) उद्देश्य-वार

परियोजनाओं के उद्देश्य-वार पैटर्न से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत में ग्रीन फील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा 93.1 प्रतिशत था जो कि अतीत में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। कुल परियोजना लागत का 6.1 प्रतिशत का मामूली हिस्सा विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए निर्देशित किया गया था (अनुबंध सारणी ए 6)।

iii) उद्योग-वार

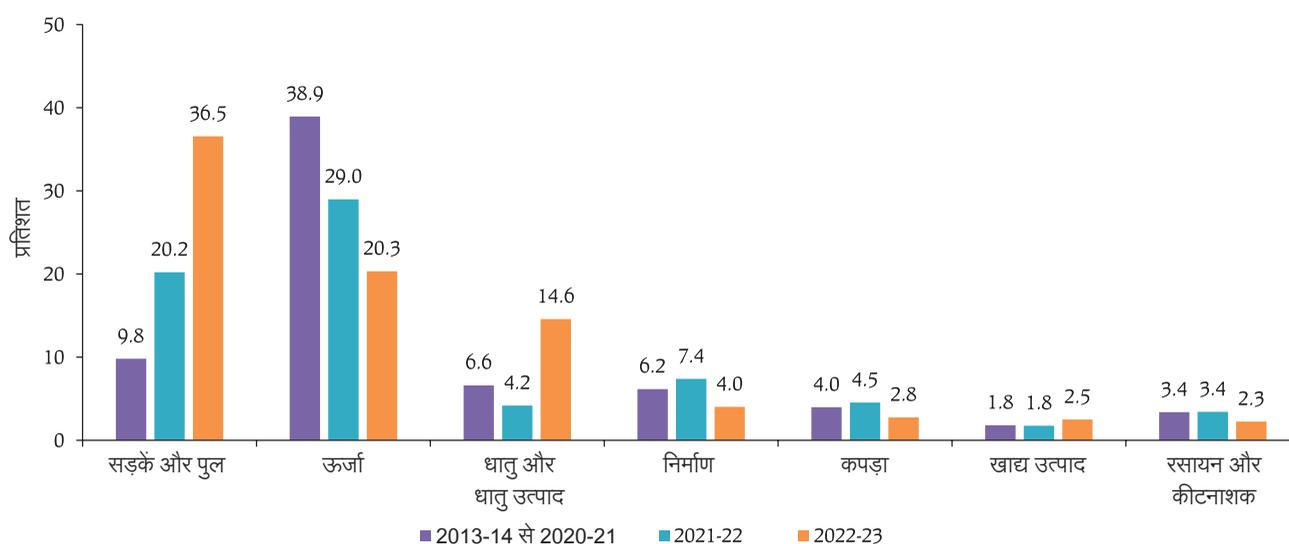
बुनियादी ढांचा क्षेत्र, जिसमें (ए) बिजली, (बी) दूरसंचार, (सी) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (डी) भंडारण और जल प्रबंधन, (ई) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क और (एफ) सड़कें और पुल शामिल हैं, 2022-23 के

दौरान परियोजनाओं की कुल लागत में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख क्षेत्र बने रहे (अनुबंध सारणी ए 7)। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के भीतर, सड़कों और पुलों की कुल परियोजना लागत में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, जिसे "भारतमाला"⁴ पहल के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के जोर देने से समर्थन मिला। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अलावा, धातु और धातु उत्पाद, निर्माण, कपड़ा और खाद्य उत्पादों जैसे प्रमुख उद्योगों का 2022-23 के दौरान परिकल्पित परियोजनाओं की कुल लागत में बड़ा हिस्सा था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में धातु और धातु उत्पादों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी (चार्ट 1)।

iv) राज्य-वार

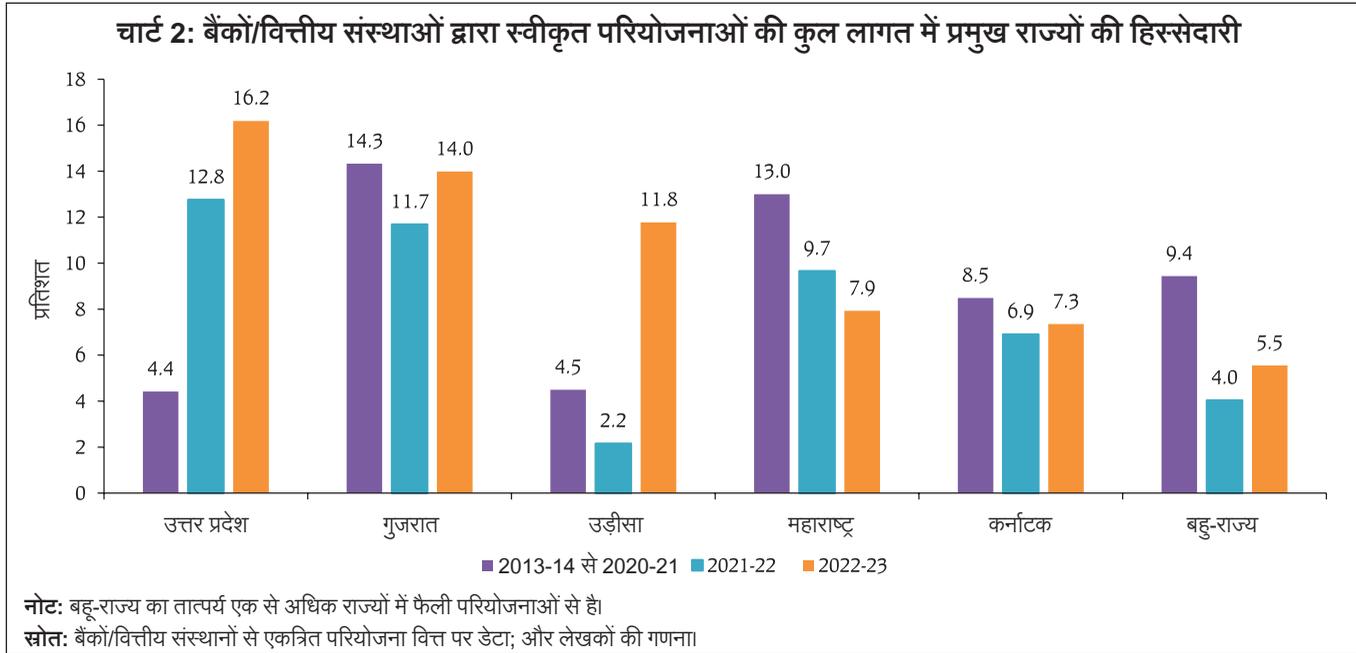
परियोजनाओं का स्थान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें कच्चे माल तक पहुंच, परियोजना की प्रकृति, कुशल श्रम की उपलब्धता, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपस्थिति, बाजार का आकार, विकास क्षमता, आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता और उत्पादों की मांग शामिल हैं। विश्लेषण के उद्देश्य से, इस लेख में, कई राज्यों में फैली परियोजनाओं को "बहु-राज्य" परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्यवार वितरण से पता चला है कि 2022-23 के दौरान शीर्ष पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुल परियोजना

चार्ट 1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी



स्रोत: बैंकों/वित्तीय संस्थानों और लेखकों की गणना से एकत्रित परियोजना वित्त पर डेटा।

⁴ भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतमाला, भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटकर देश भर में माल ढुलाई और यात्री आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।



लागत में 57.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो 2021-22 के दौरान की 43.2 प्रतिशत हिस्सेदारी से अधिक है (चार्ट 2 और अनुबंध सारणी ए 8)। 2022-23 में, बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक (16.2 प्रतिशत) थी, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान था। परियोजनाओं की कुल लागत में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष के साथ-साथ 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान दर्ज औसत हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है।

IV. निवेश इरादों की चरणबद्ध प्रोफाइल

चालू वर्ष और पिछले वर्षों के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध प्रोफाइल निजी कंपनियों का निकट-अवधि (एक वर्ष आगे) निवेश दृष्टिकोण प्रदान करता है। 2022-23 में परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध रूप से पता चलता है कि कुल प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का लगभग 33.0 प्रतिशत (₹ 87,997 करोड़) उसी वर्ष में खर्च किए जाने की उम्मीद थी, जबकि 34.7 प्रतिशत (₹ 92,539 करोड़) 2023-24 में और 24.8 प्रतिशत (₹ 66,071 करोड़) बाद की अवधि में खर्च किए जाने की संभावना है। 2022-23 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का 7.5 प्रतिशत 2022-23 से पहले ही खर्च किया जा चुका था। 2022-23 तक बैंकों/वित्तीय

संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर नियोजित पूंजीगत व्यय से, 2022-23 में परिकल्पित पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के दौरान 9.8 प्रतिशत की वृद्धि होकर 1,58,903 करोड़ रुपये हो गया (अनुबंध सारणी ए 1)।

निजी कंपनियों द्वारा ईसीबी और आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए संसाधन उनकी निवेश गतिविधियों के वित्तपोषण में सहायक होते हैं। पूंजीगत व्यय के उद्देश्य के लिए ईसीबी मार्ग के माध्यम से जुटाए गए फंड से, 2022-23 के दौरान किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 3.0 प्रतिशत की गिरावट आई और यह ₹58,186 करोड़ रुपये रह गया। पूंजी बाजार (इक्विटी रूट) ने 2022-23 में ₹2,560 करोड़ रुपये के परिकल्पित पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण को सक्षम किया, जो पिछले वर्ष (अनुबंध सारणी और ए3) की तुलना में अधिक है, हालांकि कुल परिकल्पित पूंजीगत व्यय में इसकी हिस्सेदारी बहुत न्यूनतम रही।

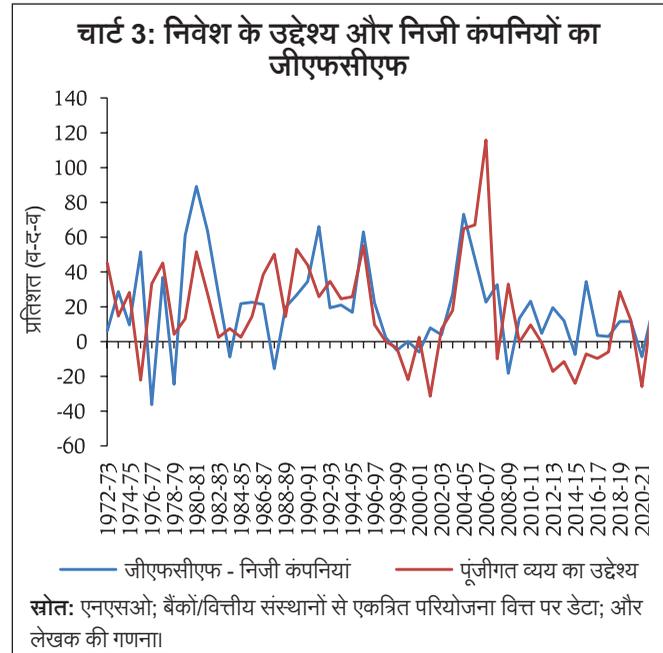
कुल मिलाकर, वित्त पोषण के विभिन्न चैनलों के माध्यम से ₹2,19,649 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश, जैसा कि पहले बताया गया था, 2022-23 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा किए जाने की उम्मीद थी, जिसमें पिछले वर्ष के नियोजित चरणों से 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, मुख्य रूप से ईसीबी के माध्यम से पूंजी निवेश में गिरावट की भरपाई करने की तुलना में अधिक

बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में वृद्धि हुई है। संदर्भ वर्ष से पहले पिछले वर्षों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं⁵ के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध प्रोफाइल 2022-23 में ₹70,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में ₹1,17,182 करोड़ रुपये हो गया।

v. निजी कंपनियों के निवेश के इरादे और जीएफसीएफ

सभी स्रोतों के माध्यम से परियोजना वित्त आंकड़ों के आधार पर परिकल्पित पूंजी निवेश, दिशा में विचलन के एपिसोडिक अवसरों को छोड़कर, निजी कंपनियों द्वारा वर्तमान कीमतों पर सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की वृद्धि को अच्छी तरह से ट्रैक करता है (चार्ट 3)।

हालांकि, इस अवधि के दौरान, निजी कंपनियों के जीएफसीएफ के लिए परिकल्पित पूंजीगत व्यय का अनुपात (एनएस डेटा के अनुसार) काफी कम हो गया - औसत हिस्सेदारी 1971-72 से 2010-11 के दौरान 40.5 प्रतिशत से घटकर 2011-12 से 2021-22 के दौरान 15.5 प्रतिशत हो गई।



कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का डिलीवरेजिंग, निधियों के आंतरिक स्रोतों के बढ़ते उपयोग और एफडीआई जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से जुटाए गए धन के परिणामस्वरूप, अपने पूंजी निवेश के वित्तपोषण के लिए निजी कंपनियों की बैंकों/वित्तीय संस्थानों पर

बॉक्स 1: निजी कंपनियों के परिकल्पित पूंजीगत व्यय और जीएफसीएफ

निजी कंपनियों के परिकल्पित पूंजी निवेश (परियोजना वित्त डेटा के आधार पर) और जीएफसीएफ (एनएस डेटा के आधार पर) के बीच दीर्घकालिक संबंधों के अस्तित्व और अल्पकालिक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए, सह-एकीकरण के लिए ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग (एआरडीएल) दृष्टिकोण (पेसरन और शिन, 1998⁶) का उपयोग किया जाता है। त्वरण प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विलंबित सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि और भारत औसत उधार दर जैसे अन्य मैक्रो चर का भी आकलन ढांचे में उपयोग किया गया था।

बाउंड परीक्षण ने परिकल्पित पूंजी निवेश और निजी कंपनियों के जीएफसीएफ के बीच दीर्घकालिक संबंध के अस्तित्व की पुष्टि की। दीर्घकालिक संबंध से पता चलता है कि निवेश के इरादे में एक

सारणी 1 निजी कॉर्पोरेट्स के परिकल्पित पूंजीगत व्यय और जीएफसीएफ

	गुणांक	टी-स्टेट	पी-वैल्यू
चयनित मॉडल* एआरडीएल (1,3,3,1,0)			
दीर्घकालिक संबंध: आश्रित चर - निजी कॉर्पोरेट्स के जीएफसीएफ में वृद्धि			
परिकल्पित पूंजीगत व्यय	0.48	3.74	0.00
जीवीए वृद्धि	2.98	3.96	
गैर-खाद्य ऋण वृद्धि	0.82	2.23	0.04
वास्तविक डब्ल्यूएलआर#	-0.83	-0.93	0.37
स्थिरांक	-35.6	-2.36	0.03
त्रुटि सुधार (-1)	-1.24	-12.68	0.00
एडीजे आर ²	0.89		
बाउंड टेस्ट (एफ स्टैट)	20.71		
निचला और ऊपरी बाउंड क्रिटिकल वैल्यूज	10% [2.46, 3.46]	5% [2.95, 4.09]	1% [4.09, 5.53]
क्रमिक सहसंबंध एलएम-परीक्षण एफ-स्टैट (पी-वैल्यू) 2.21 (0.14)		जे-बी आंकड़े 0.85 (0.65)	विषमलैंगिकता-बीपीजी परीक्षण एफ-स्टैट (पी-वैल्यू) 0.72 (0.73)

*: लैग लंबाई का चयन शार्ज मानदंड का उपयोग करके किया जाता है।

#: डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के साथ समायोजित।

(जारी)

⁵ पाइपलाइन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो पहले से ही कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं। पाइपलाइन परियोजनाओं से पूंजीगत व्यय की परिकल्पित राशि किसी दिए गए वर्ष के लिए होती है, जिसे उस वर्ष से पहले स्वीकृत किया गया था।

⁶ एम.एच. पेसरन, वाई. शिन (1998), "एन ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड लैग मॉडलिंग अप्रोच टू कॉइन्टीग्रेशन एनालिसिस", एस. स्ट्रॉम (एड.), इकोनोमेट्रिक्स और बीसवीं सदी में आर्थिक सिद्धांत: द रनर फ्रिस्क सेंटेनियल सिम्पोजियम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, यूके (1998), पीपी. 371-413।

प्रतिशत की वृद्धि से निजी कंपनियों के जीएफसीएफ में 48 बीपीएस की वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, त्रुटि सुधार शब्द का गुणांक - दीर्घकालिक संतुलन की ओर समायोजन या अभिसरण की गति - से पता चलता है कि पिछले वर्ष से चले आ रहे असंतुलन को दोलनशील तरीके से तेज गति से ठीक किया जाएगा।

परिकल्पित पूंजीगत व्यय के अनुपात में गिरावट के बावजूद, जैसा कि परियोजना वित्त डेटा से एकत्र किया गया है, अनुभवजन्य विश्लेषण अभी भी बताता है कि यह निजी पूंजीगत व्यय चक्र के बारे में प्रारंभिक संकेत प्रदान करता है।

निर्भरता कम हो गई है, जो निजी कंपनियों के जीएफसीएफ के लिए परिकल्पित पूंजीगत व्यय के अनुपात में गिरावट दर्शाती है। अनुपात में गिरावट के बावजूद, परिकल्पित पूंजी निवेश अभी भी निजी पूंजी निवेश चक्र (बॉक्स 1) का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक संकेतक के रूप में उपयोगी बना हुआ है।

VI. निष्कर्ष

निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों के अलावा पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण ने निजी कंपनियों को नए पूंजी निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर निजी कंपनियों के परिकल्पित पूंजी निवेश में 2019-20 और 2020-21 के दौरान नरमी के बाद लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि हुई है। 2022-23 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत बढ़कर ₹2,66,547 करोड़ के ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने 'सड़क और पुल' और 'बिजली' क्षेत्रों की अगुवाई में अधिकतम पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को आकर्षित करना जारी रखा है, जो बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में सरकार के प्रयास को दर्शाता है। परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 35 प्रतिशत 2023-24 के दौरान और लगभग 25 प्रतिशत उसके बाद की अवधि में खर्च किए जाने की संभावना

है। सभी तीन चैनलों के माध्यम से पाइपलाइन परियोजनाओं के वित्त पोषण के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध प्रोफाइल से पता चलता है कि परिकल्पित पूंजीगत व्यय 2022-23 में ₹94,876 करोड़ की तुलना में 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹1,71,568 करोड़ हो गया। इसके अलावा, अनुभवजन्य विश्लेषण ने निकट अवधि के निजी कॉर्पोरेट निवेश दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक संकेतक के रूप में परिकल्पित पूंजी निवेश (पूर्व-चरणबद्ध योजना) की उपयोगिता को रेखांकित किया।

बेहतर क्षमता उपयोग, ऋण मांग में बढ़ोतरी, और बेहतर व्यावसायिक अपेक्षाएं, जैसा कि आरबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए भविष्योन्मुखी उद्यम सर्वेक्षणों में परिलक्षित होता है, आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश गतिविधि को पुनर्जीवित करने की ओर इशारा कर रहे हैं।

नकारात्मक पक्ष यह है कि, भारत सहित विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने के कारण पूंजी की उच्च लागत, भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक अनिश्चितता, और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का जोखिम निवेश गतिविधियों को बाधित कर सकता है। कुल मिलाकर, निवेश चक्र आगे चलकर गति प्राप्त करने के लिए तैयार प्रतीत होता है, लेकिन, इसकी स्थिरता पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है।

सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्धता

स्वीकृति वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृति वर्ष में परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	संशोधन/रद्दीकरण के कारण परियोजना लागत [^] (₹ करोड़ में)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013-14 तक				1,70,603	93,658	34,172	14,421	4,722	1,472						
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)	14,822	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036					
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)	3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220				
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)	1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	4,001	2,086			
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)		620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	10,202	2,342	242		
2018-19	409	1,76,581	1,59,189 (9.8)			569	6,862	11,000	59,973	47,080	21,248	9,759	2,663	35	
2019-20	320	2,00,038	1,75,830 (12.1)					4,049	14,524	53,978	58,556	28,116	14,114	2,299	194
2020-21	220	75,558	75,558 (0.0)						2,491	3,709	29,013	26,166	9,711	3,867	601
2021-22	401	1,43,314	1,41,976 (0.9)							3,610	10,543	59,622	44,176	18,442	5,583
2022-23	547	2,66,547								1,127	2,150	16,663	87,997	92,539	66,071
कुल योग^{&}				1,90,564	1,40,253	1,38,595	1,43,077	1,33,172	1,46,665	1,43,025	1,35,933	1,44,754	1,58,903	1,17,182	72,449
प्रतिशत परिवर्तन					-26.4	-1.2	3.2	-6.9	10.1	-2.5	-5.0	6.5	9.8	#	

&: कॉलम का योग उन परियोजनाओं को कवर करते हुए एक विशेष वर्ष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाता है जिन्हें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। यह अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए से भिन्न हैं।

#: 2023-24 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2023-24 में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

^: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संशोधन/निरस्तीकरण का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्त पोषित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की चरणबद्धता **

अनुबंधित ऋण ↓	जारी किए गए एलआरएन की संख्या	कुल अनुबंधित ऋण (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2013-14 तक			78,864	27,376	4,896									
2014-15	478	57,327		36,791	16,806	3,151	575	2	2					
2015-16	314	38,885			28,998	7,311	2,572	4						
2016-17	346	22,154				14,953	6,005	1,192	2	2				
2017-18	419	37,896					17,822	13,054	6,484	529	7			
2018-19	515	72,490						46,221	17,725	1,236	5,398	1,844	66	
2019-20	495	95,491							65,367	17,157	11,717	965	285	
2020-21	362	40,564								21,865	13,574	3,219	1,675	231
2021-22	363	51,059								13	29,315	16,554	5,089	88
2022-23	393	82,448										35,604	44,132	2,712
कुल^{&}			78,864	64,167	50,700	25,415	26,974	60,473	89,580	40,802	60,011	58,186	51,247	3,031
प्रतिशत परिवर्तन				-18.6	-21.0	-49.9	6.1	124.2	48.1	-54.5	47.1	-3.0	#	

*: परियोजनाएं जिन्हें बैंक/वित्तीय संस्थानों से सहायता नहीं मिली।

** : 2016-17 के बाद से रुपया अंकित बांड (आरडीबी) को शामिल किया गया है।

#: 2023-24 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2023-24 में तैयार किए जाने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए से भिन्न हैं।

एलआरएन: ऋण पूंजीकरण संख्या।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्धता*

के दौरान जारी की गई इक्विटी ↓	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2013-14 तक			494	492	70									
2014-15	24	1,078		189	557	332								
2015-16	40	4,511		11	644	2753	849	183	71					
2016-17	29	1,159			14	471	368	163	143					
2017-18	51	1,538					419	327	787	5				
2018-19	39	609						506	90	13				
2019-20	12	53						2	49	2				
2020-21	12	663								139	421	84	19	
2021-22	27	3,410								10	757	1,304	939	400
2022-23	42	3,629										1,172	2,181	276
कुल*			494	692	1,285	3,556	1,636	1,181	1,140	169	1,178	2,560	3,139	676
प्रतिशत परिवर्तन				40.1	85.7	176.7	-54	-27.8	-3.5	-85.2	597	117.3	#	

*: परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/एफआई/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता नहीं मिली।

#: 2023-24 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2023-24 में लागू होने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान केवल अनुमानित निवेश को शामिल करते हुए प्रत्याशित है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/वित्तीय संस्थानों/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी*/आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

स्वीकृति वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2013-14 तक			2,49,961	1,21,526	39,138	14,421	4,722	1,472						
2014-15	828	1,45,658	14,822	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038					
2015-16	700	1,35,177	3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220				
2016-17	916	2,02,562	1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8,711	4,003	2,086			
2017-18	955	2,07,673		620	15,184	12,445	81,242	54,817	30,038	10,736	2,349	242		
2018-19	963	2,32,288					11,000	1,06,700	64,895	22,497	15,157	4,507	101	
2019-20	827	2,71,374					4,049	14,526	1,19,394	75,715	39,833	15,079	2,584	194
2020-21	594	1,16,785						2,491	3,709	51,017	40,161	13,014	5,561	832
2021-22	791	1,96,445							3,610	10,566	89,694	62,034	24,470	6,071
2022-23	982	3,52,624							1,127	2,150	16,663	1,24,773	1,38,852	69,059
कुल*			2,69,922	2,05,112	1,90,580	1,72,048	1,61,782	2,08,319	2,33,745	1,76,904	2,05,943	2,19,649	1,71,568	76,156
प्रतिशत परिवर्तन				-24.0	-7.1	-9.7	-6.0	28.8	12.2	-24.3	16.4	6.7	#	

*: रुपया मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।

#: 2023-24 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2023-24 में स्वीकृत होने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान केवल अनुमानित निवेश को शामिल करते हुए प्रत्याशित है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

सारणी ए5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2013-14 से 2022-23

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और शेयर	₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़	₹ 5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	306 8.3	115 20.0	25 13.9	21 29.1	5 28.7	472 100 (1,27,328)
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	223 9.0	65 16.6	18 14.6	19 47.8	1 12.0	326 100 (87,253)
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	214 8.6	76 20.9	34 26.0	21 38.5	1 5.9	346 100 (91,781)
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	287 5.8	180 23.3	29 11.9	40 41.7	5 17.4	541 100 (1,79,239)
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	263 5.2	149 21.0	28 10.8	42 43.8	3 19.1	485 100 (1,68,239)
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	220 4.8	110 17.0	39 17.0	36 39.6	4 21.6	409 100 (1,59,189)
2019-20	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	150 3.3	84 11.9	45 18.6	36 37.4	5 28.8	320 100 (1,75,830)
2020-21	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	128 5.5	52 16.8	15 14.2	24 53.5	1 10.0	220 100 (75,558)
2021-22	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	200 5.6	127 20.0	36 19.6	36 46.9	2 7.9	401 100 (1,41,976)
2022-23	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	264 3.9	156 13.6	51 14.1	68 41.3	8 27.1	547 100 (2,66,547)

नोट: i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत हैं।

ii. प्रतिशत शेयर परियोजनाओं की कुल लागत में शेयर है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत शत प्रतिशत नहीं हो सकता है।

सारणी ए6: 2013-14 से 2022-23 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और शेयर	नया	विस्तार और आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	361 65.2	95 20.1	2 -	14 14.7	472 100 (1,27,328)
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	203 39.4	92 14.7	2 0.2	29 45.7	326 100 (87,253)
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	260 73.6	64 14.3	3 0.1	19 12.0	346 100 (91,781)
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	429 78.6	97 9.9	4 0.1	11 11.3	541 100 (1,79,249)
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	396 89.0	80 9.5	2 0.1	7 1.5	485 100 (1,68,239)
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	309 76.8	80 19.3	- -	20 3.9	409 100 (1,59,189)
2019-20	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	262 79.8	37 13.7	1 -	20 6.4	320 100 (1,75,830)
2020-21	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	181 94.1	38 5.9	1 -	- -	220 100 (75,558)
2021-22	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	312 89.1	88 10.8	1 0.1	- -	401 100 (1,41,976)
2022-23	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	440 93.1	101 6.1	- -	6 0.8	547 100 (2,66,547)

नोट: i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत हैं।

ii. प्रतिशत शेयर परियोजनाओं की कुल लागत में शेयर है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत शत प्रतिशत नहीं हो सकता है।

iii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण: 2013-14 से 2022-23

उद्योग	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर																		
अवसंरचना	87	39.7	74	48.9	108	72.0	204	62.5	150	51.7	122	60.3	99	61.5	63	74.3	95	56.4	135	59.9
i) बिजली	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	78	26.8	47	32.9	35	49.3	58	29.0	53	20.3
ii) दूरसंचार	1	-	1	4.9	1	0.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	4	14.2	4	8.4	1	0.1	2	5.9	2	0.4
iv) भंडारण और जल प्रबंधन	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	13	5.7	4	0.4	5	1.2	2	0.2	3	0.8
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	11	3.2	8	1.3	5	2.2	3	1.1	8	1.9
vi) सड़कें और पुल	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	16	10.4	36	18.5	17	21.5	30	20.2	69	36.5
धातु और धातु उत्पाद निर्माण	44	17.4	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	16	3.0	14	0.8	6	0.8	27	4.2	60	14.6
कपड़ा	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	26	2.3	44	11.4	27	4.8	22	7.4	35	4.0
खाद्य उत्पाद	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	27	3.4	11	0.5	15	1.8	56	4.5	42	2.8
रसायन और कीटनाशक	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.4	32	1.9	20	1.5	25	1.8	40	2.5
फार्मास्यूटिकल्स	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	19	2.9	12	1.3	9	1.6	20	3.4	16	2.3
खनन और उत्खनन	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.6	9	0.6	7	0.5	20	1.3	30	2.1
आईटी सॉफ्टवेयर	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	7	1.8
विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स	3	0.1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	0.7	1	-	-	-	2	0.6	4	1.2
विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स	9	2.0	7	0.2	2	0.2	9	0.2	6	0.2	1	0.1	4	-	1	0.1	5	4.0	9	1.1
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं	10	0.7	2	0.1	1	-	22	1.1	18	1.8	15	2.6	12	0.7	7	0.3	19	2.3	20	1.1
कोक और पेट्रोलियम उत्पाद	1	0.5	1	3.4	2	2.0	2	0.5	1	0.4	-	-	3	8.0	-	-	7	1.0	17	1.1
कांच और मिट्टी के बर्तन	11	0.3	19	0.7	8	0.5	19	0.6	20	0.8	2	-	-	-	12	0.6	8	0.7	5	1.0
रबर और प्लास्टिक उत्पाद	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	5	0.5	5	0.3	17	2.1	12	0.8	13	0.8
सीमेंट	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	10	5.1	2	0.1	5	1.3	3	3.3	2	0.8
अन्य*	123	15.3	59	9.5	68	8.4	68	7.2	76	8.5	113	16.0	72	12.9	31	10.3	79	8.2	112	3.0
कुल	472	100	326	100	346	100	541	100	485	100	409	100	320	100	220	100	401	100	547	100
परियोजना की कुल लागत ₹ करोड़ में	1,27,328		87,253		91,781		1,79,249		1,68,239		1,59,189		1,75,730		75,558		1,41,976		2,66,547	

*: इसमें परिवहन सेवाएं, परिवहन उपकरण, होटल और रेस्तरां, कागज और कागज उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियां, इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक मशीनरी का विनिर्माण, चीनी और संबद्ध उत्पाद, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, मुद्रण और प्रकाशन, अन्य विनिर्माण और अन्य सेवाएं जैसे उद्योग शामिल हैं।

नोट: i. प्रतिशत शेयर परियोजनाओं की कुल लागत में शेयर है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत शत प्रतिशत नहीं हो सकता है।

ii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण: 2013-14 से 2020-21

	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर																		
उत्तर प्रदेश	21	1.1	20	5.4	15	2.5	22	3.7	30	2.4	28	4.8	24	5.4	30	13.7	33	12.8	45	16.2
गुजरात	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	56	11.1	47	15.1	54	17.1	82	11.7	82	14.0
उडिसा	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	3.0	9	1.4	6	1.9	2	0.1	9	2.2	12	11.8
महाराष्ट्र	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	34	11.5	41	6.9	13	8.5	44	9.7	48	7.9
कर्नाटक	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	34	5.7	33	17.2	11	6.1	24	6.9	37	7.3
मध्य प्रदेश	30	6.1	14	3.9	21	7	18	7.5	10	0.7	12	1.6	10	1.2	19	2.8	18	4.2	35	5.0
तमिलनाडु	33	5.4	27	2.9	26	9.3	23	4.4	28	6.6	32	12.8	28	8.3	7	0.7	40	8.8	44	4.8
आंध्र प्रदेश	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.1	12	4.0	7	15.0	11	2.1	27	4.4
जम्मू और कश्मीर	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	11	0.4	3	0.3	5	0.2	5	0.2	23	3.1
राजस्थान	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	21	7.7	23	3.8	21	17.1	32	12.6	22	3.1
पंजाब	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	15	1.9	9	0.8	4	0.7	15	2.1	21	2.5
हिमाचल प्रदेश	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	-	8	2.3	7	0.3	6	0.1	4	0.2	7	1.2	11	2.2
तेलंगाना	-	-	-	-	10	3.8	51	5.5	17	1.9	26	9.1	12	4.0	9	1.9	16	3.4	30	1.9
झारखंड	4	0.3	2	0.7	5	0.3	1	-	3	0.3	2	0.5	4	9.4	1	0.2	6	0.8	12	1.9
बिहार	6	0.2	4	0.1	6	0.2	4	0.2	3	0.1	6	0.4	6	3.4	1	-	5	3.4	6	1.6
छत्तीसगढ़	16	10.7	8	7.4	8	4.6	15	4.0	7	4.8	6	0.9	6	0.2	3	1.2	4	0.8	8	1.4
पश्चिम बंगाल	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	13	1.1	7	0.9	3	0.4	11	2.6	16	1.0
हरियाणा	15	1.1	11	1.9	16	3.6	13	1.6	21	0.5	18	1.7	20	3.4	15	7.8	14	2.0	14	1.0
केरल	3	-	4	0.2	4	0.1	6	2.7	3	0.1	6	0.9	3	1.0	-	-	5	4.2	12	0.9
गोवा	-	-	-	-	1	-	3	0.6	2	1.9	3	1.8	2	0.1	-	-	3	3.0	3	0.8
असम	4	0.3	2	0.2	4	0.4	10	0.6	5	0.8	4	0.2	1	0.3	3	4.4	2	-	6	0.7
बहु-राज्य #	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	15	9.8	8	11.7	2	1.4	7	4.0	10	5.5
अन्य*	14	0.7	10	1.2	8	1.3	20	1.0	19	4.0	22	3.3	9	0.6	6	0.5	8	1.3	23	0.9
कुल	472	100	326	100	346	100	541	100	485	100	409	100	320	100	220	100	401	100	547	100
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)	1,27,328		87,253		91,781		1,79,249		1,68,239		1,59,189		1,75,830		75,558		1,41,976		2,66,547	

#: कई राज्यों में परियोजनाएं शामिल हैं।

*: शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

नोट: i. प्रतिशत शेयर परियोजनाओं की कुल लागत में शेयर है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत शत प्रतिशत नहीं हो सकता है।

ii. -: शून्य/नगण्य।